जनजातीय छात्रावासों में खाद्य सामग्री खरीद पर सदन में हंगामा

नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति के बाद स्पीकर देवनानी ने दिए जांच के आदेश

-विधानसभा संवाददाता-

- मंत्री खराडी ने सदन में कहा कि प्रकरण की जांच के लिए वित्तीय सलाहकार, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी और सहायक लेखाधिकारी की जांच कमेटी गठित की गई है

जयपुर। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विधानसभा में कहा कि जनजातीय क्षेत्रीय छात्रावासों में खाद्य सामग्री की खरीद में अनियमितताओं की जानकारी मिलने पर जांच के लिए समिति गठित की गई है। समिति में वित्त सलाहकार, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी और सहायक लेखाधिकारी को शामिल किया गया है। मंत्री खराड़ी ने सदन में आश्वासन दिया कि जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अर्जुन बामणिया ने उठाए गए पूरक प्रश्नों के दौरान गरमाया।

बहस के दौरान विधायक बामणिया ने विभिन्न छात्रावासों में खाद्य सामग्री की दरों में अंतर का मुद्दा उठाया। मंत्री दरों का स्पष्ट अंतर नहीं बता सके, जिस पर विपक्ष ने उन्हें घेरने का प्रयास किया। बामणिया ने आरोप लगाया कि अलग-अलग हॉस्टलों में अलग दरों पर खरीद हुई है और बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए भुगतान किया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 50 हजार रुपये से अधिक की खरीद टैंडर प्रक्रिया से होनी चाहिए थी, लेकिन वार्डनों को खरीद के अधिकार देकर मनमानी दरों पर खरीद की गई। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अलग-अलग छात्रावासों में घी 800 रुपये, 550 रुपये और 408 रुपये प्रति लीटर तक खरीदा गया, जो गंभीर अनियमितता दर्शाता है।

सदन में तीखी नोकझोंक और हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया।

उन्होंने मंत्री को पूरे मामले की गहन जांच कराने के निर्देश दिए और बिना अनुमति बोलने वाले विधायकों को कड़ी फटकार लगाई।

मंत्री खराड़ी ने जवाब देते हुए कहा कि, बच्चों को समय पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खरीद की गई थी और जहां दरें अधिक पाई गई हैं, वहां जांच कराई जा रही है।

जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी और बिना जांच भुगतान नहीं किया जाएगा। बिना टैंडर खाद्य सामग्री खरीद के मुद्दे पर सदन में काफी देर तक नोकझोंक जारी रही, जिसके बाद स्पीकर के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ।

इससे पपूर्व मंत्री खराड़ी ने बताया कि विभाग ने छात्रावासों को सहकारिता उपभोक्ता भंडार से खाद्य सामग्री खरीदने के निर्देश दिए थे, लेकिन भंडार द्वारा 2 माह बाद राशन उपलब्ध कराने में असमर्थता जताने पर छात्रावासों के लिए बाहर से सामग्री खरीदी।

आश्रम छात्रावास सल्लोपाट (बांसवाड़ा) को 3.42 लाख रुपये का भुगतान किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2024-25 और 2025-26 में खाद्य सामग्री आपूर्ति के लिए निविदाएं जारी नहीं की गई थीं। संबंधित छात्रावासों-सल्लोपाट व खेडावड़लीपाड़ा (बांसवाड़ा), सुहागपुरा (प्रतापगढ़) और रघुनाथपुरा (डूंगरपुर) के अगस्त से सितंबर 2025 तक के बिलों की प्रतियां सदन में रखी गई।

नगर निगम में रिश्वत लेते ट्रैप हुए दोनों डॉक्टर निलंबित

जयपुर। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बुधवार को रिव्यू मीटिंग में साफ चेताया कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने नगर निगम जयपुर में एसीबी द्वारा ट्रैप किए गए पशुपालन विभाग के 2 डॉक्टरों को तुंरत निलंबित करने के निर्देश दिए। ज्ञात रहे कि 16 फरवरी को एसीबी ने नगर निगम जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर लगे पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा और डॉ. राकेश कलोरिया को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों ट्रैप किया था। बुधवार को डॉ. समित शर्मा ने शासन सचिवालय में अफसरों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को साफ चेतावनी दी कि, भ्रष्टाचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कहीं से भी इस तरह की कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई जगह से सरकारी दवाओं के दुरूपयोग की शिकायतें मिल रही हैं, उसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाएं।

मुख्यमंत्री ने सूर्यकिरण और सारंग एरोबेटिक शो के बारे में चर्चा की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वायुसेना के अधिकारियों से जयपुर में होने वाले सूर्यकिरण और सारंग एरोबेटिक शो के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 20 एवं 22 फरवरी को जल महल की पाल पर प्रस्तावित एरोबेटिक शो में सूर्यकिरण डिसप्ले टीम के विमान और सारंग डिस्पले टीम के हेलिकॉप्टर्स हिस्सा लेंगे। इनके द्वारा ट्राई कलर स्मोक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इन रोमांचकारी हवाई प्रदर्शनों से आम जनता को रूबरू कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। लगभग 50 हजार दर्शक क्षमता के लिए जल महल की पाल पर व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, स्टेशन कमांडर विनय भारद्वाज, विंग कमांडर अजय दशरथी और अभिजीत सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वायुसेना के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को छायाचित्र भी भेंट किए।

राजस्थान में 200 बांध तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रु. स्वीकृत

जयपुर (विसं)। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वर्ष 2026-27 में प्रथम चरण में लगभग 200 जीर्ण-शीर्ण बांधों और तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रश्नकाल के दौरान विधायक घनश्याम के पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य जल संरचनाओं को सुदृढ़ कर सिंचाई क्षमता बढ़ाना और जल संरक्षण को मजबूत करना है। मंत्री ने जानकारी दी कि टोडाभीम क्षेत्र के बिशन समंद बांध एवं उससे संबंधित नहर का निर्माण कार्य वर्ष 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसके लिए 12 अगस्त 2025 को प्रशासनिक स्वीकृति के साथ 229.69 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त 2025 को प्रथम निविदा आमंत्रित की गई, लेकिन किसी भी बिडर ने भाग नहीं लिया। इसके बाद पुन: निविदा प्रक्रिया अपनाई गई और 24 नवम्बर 2025 को तकनीकी मूल्यांकन के बाद वर्क ऑर्डर जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया।

सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम जयपुर के आसमां में बिखेरेगी रोमांच

जयपुर। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम जयपुर के लोगों को हवाई कौशल, अनुशासन और टीमवर्क का अद्भुत प्रदर्शन दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपनी रंगीन हेलीकॉप्टरों और शानदार फॉर्मेशन फ्लाइंग के लिए प्रसिद्ध यह टीम 19-20 फ़रवरी तक अभ्यास उड़ानें भरेगी, जबकि अंतिम प्रदर्शन 22 फ़रवरी को किया जाएगा।

'सारंग'-संस्कृत में जिसका अर्थ मोर है- भारतीय वायुसेना का गौरवशाली ब्रांड एंबेसडर है, जो इसके एयर वॉरियर्स की पेशेवर दक्षता और उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। स्थापना के बाद से ही सारंग ने अपनी विशिष्ट समन्वित एरोबेटिक कलाबाज़ियों से दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है।

टीम ने वर्ष 2004 में सिंगापुर में एशियन एयरोस्पेस शो में अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदार्पण किया और तब से अब तक विश्व के 390 से अधिक स्थानों पर 1200 से ज्यादा प्रदर्शन कर चुकी है।

सारंग टीम स्वदेशी रूप से निर्मित 'ध्रुव' एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर पर उडान भरती है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिज़ाइन और विकसित किया है। यह टीम अत्यंत फुर्तीले

वैरिएंट का संचालन करती है। 'ध्रुव' एक ऑल-वेदर, मल्टी-मिशन सक्षम हेलीकॉप्टर है और 'आत्मनिर्भरता' की भावना का सशक्त प्रतीक भी है-जो भारत की तकनीकी क्षमता और विमानन उत्कृष्टता को दर्शाता है।

जब सारंग टीम जयपुर के आकाश को रंगों से सजाएगी, तब पिंक सिटी में विरासत और उच्च-स्तरीय विमानन का दुर्लभ संगम देखने को मिलेगा। शाही किलों और महलों की कालातीत पृष्ठभूमि में दर्शक एक ऐसे रोमांचक नज़ारे की अपेक्षा कर सकते हैं, जहाँ सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग और शहर की जीवंत आत्मा का सुंदर मेल होगा-जो साहस, कौशल और राष्ट्रीय गौरव, भारतीय वायुसेना की स्थायी पहचान, का उत्सव मनाएगा।

कान्हा रेस्टोरेंट समूह के 33 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी

आयकर टीमों ने जयपुर स्थित 26 ठिकानों के साथ-साथ श्रीगंगानगर, करौली, कोटा, हिंडौन और मुंबई स्थित कार्यालयों व अन्य परिसरों में दबिश दी

-कार्यालय संवाददाता-

- प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आयकर अधिकारियों ने बैंक खातों, डिजिटल रिकॉर्ड, नकदी लेन-देन और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की। साथ ही कई महत्वपूर्ण फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डाटा जब्त किए जाने की जानकारी है।
- प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बड़े पैमाने पर आयकर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका के चलते यह कार्रवाई की गई है। जांच पूरी होने के बाद ही कर चोरी की वास्तविक राशि का खुलासा हो सकेगा

जयपुर। राजस्थान की चर्चित फूड चेन कान्हा रेस्टोरेंट समूह पर आयकर विभाग ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश सहित अन्य राज्यों में 33 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यह कार्रवाई बुधवार सुबह शुरू हुई जो अब तक जारी है।

आयकर विभाग के अनुसार सबसे अधिक 26 ठिकानों पर जयपुर में जांच की जा रही है। इसके अलावा श्रीगंगानगर, करौली, कोटा, हिंडौन और मुंबई स्थित कार्यालयों व अन्य परिसरों में भी आयकर टीमों ने दबिश दी। अधिकारियों ने बैंक खातों, डिजिटल रिकॉर्ड, नकदी लेन-देन और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की। कई महत्वपूर्ण फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डाटा जब्त किए जाने की जानकारी है।उदयपुर में जगदीश मंदिर के पीछे स्थित सन एंड मून रेस्टोरेंट और हरिदास जी मगरी स्थित द सिएरा सोल रेस्टोरेंट पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। बताया जा रहा है कि दोनों प्रतिष्ठानों का स्वामित्व एक ही समूह के पास है।

सिएरा होटल में 29 कमरे हैं, जहां से खातों और लेन-देन से संबंधित दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में नेशनल हाईवे स्थित फैटम रेस्टोरेंट पर भी आयकर विभाग ने पुलिस जाब्ते के साथ छापा मारा और कारोबार से जुड़े रिकॉर्ड व कंप्यूटर डाटा की जांच की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बड़े पैमाने पर आयकर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका के चलते यह कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही कर चोरी की वास्तविक राशि और अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।

प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित अजमेर यात्रा पर मुख्यमंत्री ने की तैयारियों पर चर्चा

- मुख्यमंत्री ने शिलान्यास-लोकार्पण, डीबीटी और नियुक्ति पत्र वितरण के संबंध में अधिकारियों को किया निर्देशित

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा से 'विकसित राजस्थान' के संकल्प को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री इस यात्रा के तहत प्रदेशवासियों को 23 हजार 500 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण की सौगात देने के साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। शर्मा बुधवार को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित अजमेर यात्रा की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कायड विश्राम स्थली पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां आपसी समन्वय से तय समय में पूरी करें।

मुख्यमंत्री ने डोम, बैठक व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, चिकित्सा व्यवस्था, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से फीडबैक लिया।

उन्होंने इस संबंध में निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी से इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री के कर कमलों से होने वाले डीबीटी कार्यक्रम और लाभार्थियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली एवं जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री की इस अजमेर यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी विभाग एवं जिला प्रशासन अजमेर मिलकर कार्य करें।

हनुमानगढ़-गंगानगर में बनेगी हैवी मेटल टेस्टिंग लैब

जयपुर (हि.स.)। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि पंजाब से आने वाले नहरी जल में समय-समय पर अधिक गंदलेपन की समस्या सामने आती है। नहर बंदी के दौरान जल भंडारण की स्थिति में यह समस्या बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि दूषित पानी की समस्या से निपटने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जा रही है।मंत्री ने आश्वस्त किया कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में हैवी मेटल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर पेयजल गुणवत्ता जांच के लिए टेस्टिंग लैब स्थापित करने की योजना है, जिससे जल की निगरानी अधिक प्रभावी हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ जल संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।प्रश्नकाल के दौरान विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर के पूरक प्रश्नों के उत्तर में मंत्री ने बताया कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की जल मांग 7.9 एमएलडी तथा ग्रामीण क्षेत्र की 9.2 एमएलडी है।

चर्चा में भाग लेने वाले विधायक मंत्री के उत्तर तक सदन में अनिवार्य उपस्थित रहें : देवनानी

स्पीकर ने निर्देश दिए कि जब किसी भी अनुदान की मांग पर संबंधित मंत्री उत्तर देते हैं, उस समय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को सदन की कार्यवाही के सुचारु संचालन एवं मर्यादा के पालन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। देवनानी ने कहा कि जिन सदस्यों के नाम चर्चा में भाग लेने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, वे मंत्री के उत्तर तक सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। चर्चा केवल अपने विचार व्यक्त करने तक सीमित न रहे, बल्कि मंत्री के उत्तर को सुनना भी प्रत्येक सदस्य का दायित्व है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीमित कार्य दिवसों के दौरान सदन में सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अक्सर कोरम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करती है। सभी सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित है. विशेषकर वे सदस्य जिनका नाम चर्चा के लिए निर्धारित है।

अध्यक्ष देवनानी ने यह भी निर्देशित किया कि जब किसी भी अनुदान की मांग पर संबंधित मंत्री उत्तर देते हैं, उस समय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि 16 अनुदान मांगों पर अलग-अलग मंत्रियों को उत्तर देना होता है, ऐसे में मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों का भी सदन में उपस्थित रहकर चर्चा सुनना संसदीय परंपरा और मर्यादा के अनुरूप है। अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि जिस दिन संबंधित मांग सदन में ली जाती है, उस दिन प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत माने जाएंगे। बोलने की अनुमति उन्हीं सदस्यों को दी जाएगी, जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतकों एवं सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा आसन को भेजे जाएंगे। प्राथमिकता उन सदस्यों को दी जाएगी, जिनके कटौती प्रस्ताव सूचीबद्ध हैं। मतदान के समय यह परंपरा रही है कि प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वत: वापस माने जाते हैं। जिस सदस्य का नाम पुकारा जाएगा, वे अपने सभी कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय अपने विचार रखेंगे। पार्टी के नेता अथवा अन्य प्रमुख सदस्य भी अपनी पार्टी की ओर से विचार व्यक्त कर सकेंगे।

स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बुधवार को सदन की गरिमा एवं अनुशासन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अध्यक्ष देवनानी ने यह भी स्पष्ट किया कि मांगों पर बहस के दौरान उठाए गए प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्री उसी दिन देंगे। इसके पश्चात मांगों पर मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। समयाभाव के कारण जिन प्रश्नों का उत्तर तत्काल नहीं दिया जा सकेगा, उनका लिखित उत्तर संबंधित सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रदेश में भजनलाल सरकार का फोकस "डिजिटल शासन-पारदर्शी प्रशासन"

राजस्थान सम्पर्क से 98 प्रतिशत से अधिक परिवाद हुए निस्तारित

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट में डिजिटल शासन और पारदर्शी प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जो जनसेवा के उच्चतम मापदंड स्थापित करने में कारगर होंगे।

बजट में नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है, जिसमें "वन्स ओनली प्रिंसिपल" लागू किया जा रहा है।

इसमें नागरिकों एवं उद्यिमयों से सिर्फ एक बार ही दस्तावेज लिया जाएगा, जिसे विभाग आपस में साझा करेंगे। इसी प्रकार, लोक कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता निर्धारण को बेहतर बनाने के लिए जनाधार डेटाबेस को विभिन्न विभागों के मापदंडों और पोर्टल्स से जोड़ने का प्रावधान भी किया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

गया है। इससे पात्र नागरिकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकेगी।

राज्य सरकार ने बजट में प्रमुख सेवाओं को वाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू किया जाएगा, जिससे आमजन को 100 प्रमुख सेवाएं मिल सकेगी। इसी प्रकार, 25 हजार युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई-मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा, जो मोबाइल आधारित सेवाएं प्रदान करेंगे।

वहीं, सभी नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सेवा केन्द्र स्थापित कर आमजन को जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, फायर एनओसी एवं अन्य अनुज्ञा पत्र संबंधी सेवाएं ऑनलाइन करने का प्रावधान भी किया गया है।

राज्य सरकार ने डिजिटल राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीन आईटी पॉलिसी की महत्वपूर्ण घोषणा की है।

वहीं, स्टेट डेटा सेंटर की विभिन्न सेवाएं स्टार्टअप्स, एमएसएमई और नागरिकों को किफायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटेशन पॉलिसी और आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, कृषि एवं पर्यावरण निगरानी में निर्णय क्षमता संवर्धन के लिए जिओ स्पेसियल पॉलिसी की घोषणा भी की गई है। परिणामोन्मुखी जनकल्याणकारी योजनाओं और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए सीएम-प्रमाण (पॉलिसी, रिसर्च एंड एनालिटिक्स फोर मेजरेबल एक्शन एण्ड नेक्सस) यूनिट स्थापित की जाएगी।

वहीं, नीति आयोग की तर्ज पर गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉरमेशन एण्ड इनोवेशन (रीती) के 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नागरिकों के लिए सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार करने के लिए में राजकीय कार्यालयों का निरंतर निर्माण और उन्नयन हो रहा है।

गुजरात में हुई "सहकार मंथन" बैठक में राजस्थान के नवाचारों की सराहना

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत गुजरात के गांधीनगर में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 17 फरवरी को 'सहकार मंथन' बैठक आयोजित हुई। राजस्थान से सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने इस बैठक में सहभागिता की।

दक ने बताया कि 'सहकार से समृद्धि' की दिशा में राज्य में किये जा रहे कार्यों एवं नवाचारों को बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। विशेष रूप से विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के बेहतर क्रियान्वयन, सहकारी समितियों द्वारा मिलेट आउटलेट्स खोले जाने, राष्ट्रीय स्तर पर गठित बहुराज्यीय सहकारी समितियों की राज्य

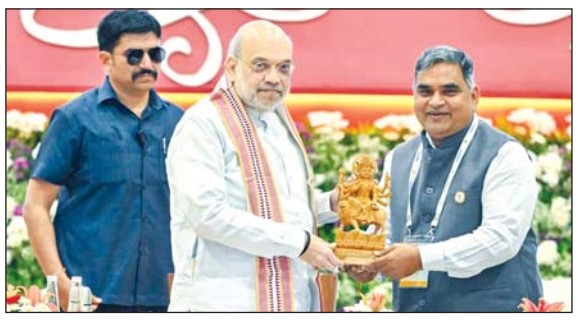

केंद्रीय मंत्री अमित शाह का स्वागत प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने किया।

की सहकारी समितियों द्वारा सदस्यता, नवीन एम-पैक्स के गठन, उदयपुर में बाइक ऑन रेंट सेवा शुरू किए जाने एवं सहकार सदस्यता अभियान आदि के लिए राज्य की सराहना की गई। उन्होंने बताया कि विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के क्रियान्वयन में राज्य का देश में प्रथम एवं नवीन एम-पैक्स के गठन में द्वितीय स्थान है। इसी प्रकार, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि राज्य की सहकारी समितियों द्वारा अब तक 225 मिलेट आउटलेट्स खोले जा चुके हैं। दक ने बताया कि शाह ने बैठक में राज्यों को अन्न भण्डारण क्षमता बढ़ाने, सभी सहकारी संस्थाओं के बैंक खाते ज़िला सहकारी बैंकों में खोलने व केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहकारी बैंकों की भागीदारी बढ़ाने, आगामी दिनों में देश में अनाज भण्डारण क्षमता उत्पादन की तुलना में तीन गुना बढ़ाने पर बल दिया। बैठक में बताया गया कि राज्य की सहकारी समितियां ऋण वितरण के साथ सोलर एनर्जी प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वेयर हाउस, जिम, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, ड्रोन, कस्टम हायरिंग सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर एवं ई-मित्र आदि नवीन गतिविधियों को अपना रही है।